A Hindi Cell has been functioning for some time past in the Directorate General of Shipping for the purpose of translating various rules and regulations under the Merchant Shipping Act from English to Hindi. So far, 12 sets of rules and 36 forms have been translated from English to Hindi.

Behaviour of Private Bus Operators under D.T.C. Operation

449 KUMARI KAMLA KUMARI: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government porpose to cancel the licences of all the private Bus Operators under D T.C. Operation as they never care for passengers, and

(b) if not, the reasons therefor and the action being taken to control them?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI H. M TRIVEDI): (a) No, Sir.

(b) According to the terms and conditions of the Agreement entered into with the owners of private buses, they are required to abide by the instructions and orders issued by the Corporation regarding the operation of these buses. When any irregularity like non-picking up of passengers and not stopping buses or stopping these at places other than bus stops is reported, action is taken against the concerned bus owners as per terms and conditions of the Agreement entered into with them by the Management of the Corporation.

निरोध की कीमत में वृद्धि

450. **श्री लालजी भाई :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में— 'निरोध' की कीमत 15 पैसे से बढ़ाकर 35 पैसे कर दी है ;

(ख) क्या इस मूल्य वृद्धि का 'निरोध' की बिक्री पर प्रतिकूल असर पड़ेगा तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम में बाधा पड़ेगी; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): (क) 1 अक्तूबर, 1974 से निरोध का खुदरा मूल्य 15 पैसे से बढ़ा कर 25 पैसे के तीन निरोध कर दिया गया है ;

(ख) इतनी जल्दी यह बताना सभव नही है कि निरोध के मूल्य मे परिवर्तन करने से इस की बिक्री पर क्या प्रभाव पडेगा। तथापि इसके परिणाम स्वरूप परिवार नियोजन कार्यक्रम पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पडने की सभावना नही है क्योंकि निरोध परिवार नियोजन केन्द्रो पर भी नि शुल्क उपलब्ध है ।

(ग) प्रश्न नही उठता ।

Visit by Expert Team from Europe to Select Sites for Shipbuilding Yards

451. DR. RANEN SEN: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state

(a) whether any expert team from Europe has visited various parts of India recently to find out suitable sites for building shipyards in India; and

(b) whether any report has been submitted by them, if so, the broad outlines thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI H M. TRIVEDI): (a) As per agreements entered into by the Government of India with three foreign consultants from Europe, expert teams of these consultants have recently visited the sites

recommended by the Techno-Economic Working Group set up to evaluate the various sites proposed by State Governments.

(b) No, Sir. The reports from all the three consultants are expected by the end of Feburary, 1975.

Sending of plasma abroad by some agencies of Bombay

452. DR. SARDISH ROY: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING be pleased to state:

(a) whether the Government are aware that some agencies in Bombay are clandestinely sending plasma abroad; and

(b) if so, the steps taken against those agencies?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (SHRI A. K. M. ISHAQUE): (a) The Government are not aware of any such clandestine transaction.

(b) The question does not arise

बीड़ी मजदूरों की मजूरी

453. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान महगाई को देखते हुए विभिन्न राज्यो मे बीड़ी मजदूरो को प्रति हजार बीड़ी पर मिलने वाली मजूरी बहुत कम है और वह भी सभी राज्यों में एक समान नही है; और

(ख) यदि हा, तो क्या सरकार ने उनकी समान मजूरी तथा अन्य सुविधाये निश्चित करने के लिए कोई केन्द्रीय कानून बनाने का निश्चय किया है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) :

(क) जी नही । जनवरी, 1973 में आयोजित की गई राज्य श्रम मंत्रियों की बैठक ने समान और अधिक मजदूरी की ओर पहले कदम के रूप में, बीड़ी श्रमिकों की उस समय की मजदूरियों को बढ़ाने के लिये सिफारिशें की थी । इन्हें करीब-करीब लागू कर दिया गया था । हाल में 27–28 सितम्बर 1974 को नई दिल्ली में हुये श्रम मंत्रियों के सम्मेलन ने और आगे सिफारिश की है कि बीड़ी उद्योग में 1000 बीड़ियों को लपेटने के लिए वर्तमान न्यूनतम मजदूरी दरों को 4.50 रु० और 5.00 रु० की सीमा के भीतर संशोधित किया जाए और यह कि नई दरें यथाशीघ्र लागू की जाएं तथा हर हालत में 1 मई, 1975 के बाद नही । यह भी स्वीकार किया गया कि उपर्युक्त व्यवस्थाएं किसी भी राज्य में वर्तमान अधिसूचनाओं के अन्तर्गत पहले से विद्यमान उच्चतर मजदूरियों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले होंगी ।

(ख) बीड़ी और सीगार श्रमिक (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 पहले ही बीड़ी उद्योग में कल्याण, स्वास्थ्य और अन्य लाभों की व्यवस्था करता है । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण और पुनरीक्षण की व्यवस्था करता है । इसलिए कोई और विधान बनाने का कोई प्रस्ताव नही है ।

Visit by Shah of Iran to India

454. SHRI MUHAMMED SHERIFF: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state the nature and outcome talks held between the Prime Minister of India and the Shah of Iran who visited New Delhi in October, 1974?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI BIPINPAL DAS): The Shahanshah of Iran visited India from October 2 to 4, 1974. During this visit the Shahanshah and the Prime Minister of India exchanged views on a number of international issues of mutual interest and on bilateral matters. The two leaders also reviewed and expressed satisfaction at